School of Social Science

Certificate

I hereby declare that the short synopsis"सरकारी योजनायें एवं जनजातीय विकास: जनपद सोनभद्र का एक भौगोलिक अध्ययन"(Sarkari Yojanayen Evem Janjatiya Vikas : Janpad Sonbhadra Ka Ek Bhaugolik Adhyayan) being submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Geography under school of Social Science of U.P. Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj during the academic year 2024

It is a bonafide record of original work carried out under the supervision of Prof. Sanjay Kumar Singh and has not been submitted in full or part to any other university or institute for a degree or diploma. Further, it is certified that the short synopsis is plagiarism-free and the repot has been submitted.

Amit Kr. Patel

(Signature)
Amit Kumar Patel
En.No.-2301401

(Signature)
Research Supervisor
(Prof.Sanjay Kumar Singh)
Faculty of Geography

13/5/2025
(Signature)
Prof.Santosha
Kumar
(Director of Concerned School of Studies)

13/05/25
(Signature)
Prof.P.K.Pandey
(Secretary of RDC/Director,R&DCell)

"सरकारी योजनायें एवं जनजातीय विकास जनपदः सोनभद्र का एक भौगोलिक अध्याय"

"Sarkari Yojanayen Evem Janjatiya Vikas : Janpad Sonbhadra Ka Ek Bhaugolik Adhyayan"

SHORT SYNOPSIS

Submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY IN GEOGRAPHY

to

U.P.Rajarshi Tandon Open University, Prayagraj

AMIT KUMAR PATEL

Enrollment No.-2301401

Under the Supervision of

Prof.Sanjay Kumar Singh

Faculty of Geography

School of Social Sciences

U.P. Rajarshi Tandon Open University

Shantipurm,(Sector–F)Phaphamau,Prayagraj–211021

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध संक्षिप्तका सरकार की नीतियों और योजनाओं का जनपद सोनभद्र की जनजाति पर हुए सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का आकलन करना है यह शोध संक्षिप्तका योजनाओं और नीतियों का न केवल संख्यात्मक अपितु गुणात्मक प्रभाव का भी विश्लेषण करना है इसके साथ ही उनके समाधान हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किया जाना है इस शोध संक्षिप्तका में प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग करके शोध के परिणाम तक पहुंचना आपेक्षित है। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रह साक्षात्कार,प्रश्नावली व क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा व द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह सरकारी प्रकाशन, अकादमी प्रकाशन व अन्य प्रासंगिक स्रोतों से प्राप्त किया जाएगा इस अध्ययन में सह–संबंध विश्लेषण का प्रयोग किया जाएगा। इस अध्ययन में मिश्रित शोध प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा

Keywords : योजनाओं, सामाजिक, आर्थिक, मिश्रित, नीतियों, सह–संबंध विश्लेषण

Amit Kr. Patel

CONTENTS

S. No.	Description	Page No.
1	Introduction	1-3
2	Literature Review	4-5
3	Description Broad Area	6-7
4	Objectives of the Study	8
5	Research Methodology	8
6	Expected Outcome of the Research	9
	References	
	Plagiarism Report	

प्रस्तावना

भारत में जनजातिय समुदायों के पास समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और वे देश की विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, उन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक–आर्थिक असमानताओं, बुनियादी सेवाओं, संसाधनों तक सीमित पहुँच का सामना करना पड़ा है। इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, भारत सरकार ने जनजातिय विकास को बढ़ावा देने और उनकी जीवन स्थितियों में सुधार लाने के उद्‌देष्य से कई योजनाएं और नीतियां लागू की हैं। यह शोध प्रारूप उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित जनपद–सोनभद्र में आदिवासी विकास पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव से सम्बन्धित है। अध्ययन क्षेत्र में गोंड, कोल, खैरवार, बैगा, पटारी, परेहिया, भुइया, पनिका और अन्य आदिवासी समुदायों की विविध आबादी का घर है। इन समुदायों में अद्वितीय सामाजिक संरचनाएं, भाषाएं और परंपराएं हैं, प्रायः उच्च स्तर की गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, रूढ़िवादिता, परम्परागत समाज, संसाधनों के अभाव सरकारी योजनाओं एवं लाभ से दूर, बेरोजगारी, भुखमरी, अन्धविश्वास में समाज जकड़ा है। यहां अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का अनुभव होता है।

इन चुनौतियों के जवाब में, आदिवासी आबादी के उत्थान और उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा विभिन्न सुविधाओं की पहल शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उज्जवला योजना, इन्दिरा आवास जैसी योजना द्वारा बड़े पैमाने पर विकास कार्य किया जा रहा है। इस शोध का व्यापक उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र सोनभद्र में इन सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना है, जिसमें उनके भौगोलिक प्रभाव पर विशेष जोर दिया गया है। यह अध्ययन जनपद में आदिवासी समुदायों की सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर प्रकाश डालेगा, मौजूदा नीतियों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण करेगा और उन क्षेत्रों को इंगित करेगा जिन पर ध्यान देने और सुधार की आवश्यकता है। प्राथमिक आंकडा संग्रह के संयोजन के माध्यम से, जिसमें सर्वेक्षण, साक्षात्कार और लक्षित समूह चर्चा एवं द्वितीयक आंकड़े सरकारी रिपोर्ट, जनगणना आंकड़ा और आकादमिक साहित्य जैसे माध्यमिक आंकड़ा स्रोत शामिल है, यह शोध कार्य आदिवासी विकास की वर्तमान स्थिति की समग्र विष्लेषण करने का प्रयास

Amit Kr. Patel

होगा। इसके अलावा, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) तकनीक को स्थानिक विश्लेषण, मानचित्रण और आंकड़ों के बिम्बीकरण, विश्लेषण करने के लिए नियोजित किया जायेगा, जिससे अध्ययन क्षेत्र के अन्दर आदिवासी विकास और सामाजिक–आर्थिक असमानताओं के भौगोलिक आयामों का पता लगाने में सक्षम होंगे। इस अध्ययन के निष्कर्षों से भारत में जनजातिय विकास पर चल रहे विमर्श अथवा सरकारी योजनाओं के निर्माण में एक उपयुक्त योगदान की सम्भावना है। जनजातिय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं की पहचान करके और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता का आंकलन करके, इस शोध का उद्देश्य साक्ष्य–आधारित निष्कर्ष निकालना है। जो नीतिगत निर्णयों और सामाजिक–आर्थिक उत्थान को दिषा प्रदार कर सके। अतः शोधकार्य अधिक लक्षित और प्रभावशाली विकास पहलों को आदिवासी समाज के कल्याण हेतु उपयोगी बनाना है, जो जिला सोनभद्र में आदिवासी आबादी के लिए कल्याण ओर जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक दिशा प्रदान कर सके और देश भर में आदिवासी विकास प्रयासों के लिए एक समावेशी मॉडल के रूप में उभर सकें।

सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना के अर्तगत देश में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस और समेकित विकास योजनाओं की जरूरत को महसूस किया। परिणामस्वरूप दूसरी पंचवर्षीय योंजना (1956–1961) के दौरान अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रमों को चार समूहो मे बाँटा गया जो इस प्रकार के (1) संचार (2) शिक्षा और संस्कृति (3) जनजातिय अर्थव्यस्था का विकास तथा (4) स्वास्थ, आवासन और जलापूर्ति। आर्थिक विकास पर जोर देते हुए इस बात का ध्यान रखा गया की समाज में असमानता, अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास की योजना बनाते समय उनका सामाजिक मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्यों को ध्यान में रखा गया। ये कार्यक्रम इस समुदाय की संस्कृति और परम्पराओं के प्रति सम्मान और समझदारी पर आधारित थे दूसरी योजना में शामिल योजनाओं और नीतियों को तीसरी योजना (1961–1966) में भी जारी रखा गया। चौथी योजना (1969–1974) में देशवासियों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार का संकल्प जाहिर किया गया, ताकि सब के लिए समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पाँचवी योजना (1974–1978) में विकास कार्यक्रमों का प्रत्यक्ष लाभ

Amit Kr. Patel

अनुसूचित जनजातियों तक पहुँचाने के लिए जनजातिय उपयोजना (टी0एस0पी0) शुरु कि गयी। टी0एस0पी0 का उद्देश्य सिर्फ जनजाति समुदाय के जीवन स्तर में सुधार के लिए विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने तक सीमित नही था बल्कि इस समुदाय के हितों की कानूनी और प्रशासनिक रक्षा पर भी ध्यान दिया गया। छठीं योजना (1980–1985) में कोषों का अधिक विक्रेद्रीकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस योजना में अनुसूचित जनजतियों कि कम से कम 50 प्रतिशत परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। अनुसूचित क्षेत्रे में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विस्तार किया गया। सातवीं योजना (1985–1990) के दौरान अनुसूचित जन जातियों के आर्थिक विकास के लिये दो राष्ट्रीय संस्थाओ का गठन किया गया। इनमें से एक 1987 में गठित जनजातिय सहकारी विपणन महासंघ (ट्राइफेड) हैं यह राज्य जनजातिय विकास सहकारी निगमों के लिए शीर्ष संस्था है। आठवीं योजना (1992–1997) में अनुसूचित जनजातियों के शोषण को खत्म करने के प्रयासो के साथ उनके अधिकारो के दमन, भूमि से बेदखिली, न्यूनतम मजदूरी का भूगतान नही होने तथा उन्हे छोटे वन उत्पादो के संग्रह के अधिकार से वंचित किये जाने जैसे समस्याओ के समाधान पर भी ध्यान दिया गया।

नौवी योंजना (1997–2002) में ऐसे परिवेश के निर्माण पर जोर दिया गया जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों का स्वातंत्रता से उपयोग करते हुये समाज के अन्य वर्गों के समान जीवन व्यतीत कर सकें। इसके बाद दसवीं योजना (2002–2007) में जनजातिय समाज के अनसुलझे मुद्दे और समस्याओं को समयबद्ध ढ़ंग से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

ग्यारहवीं (2007–2012) और बारहवीं (2012–2017) योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के उपायों को मजबूत करने का जोर दिया गया इसके अलावा राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए यथोचित और समुचित गतिविधियां चलाने के बारे में निर्देश दिये गये। नीति आयोंग में केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को हर साल अपने कुल योजना आबंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत तक हिस्सा जनजातिय विकास के उद्देश्य से रखने के लिए अधिकृत किया गया।

Amit Kr. Patel

साहित्य समीक्षा

- .G. Deogankar (1994) ने अपनी पुस्तिक Tribal Administration and Development में विभिन्न सरकारी प्रयासों द्वारा जनजातियों के विकास का वर्णन किया है।

- A.R. Basu & S. Nijhawavi (1994) ने अपने लेख संग्रह Tribal Development Administration in India में जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास को दर्षाया है।

- C.P. Singh (1994) ने अपने पुस्तिक Tribal Development में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातियों का सांख्यिकीय आंकड़ा प्रस्तुत किया है। इसमें जनजातिय लोगों का गैर जनजातिय लोगों द्वारा शोषण का भी वर्णन है।

- Ashok Thakur (2001) ने अपनी पुस्तिक Tribal Development & its Paradox में जनजातिय विकास व उसके विरोधाभाषों की चर्चा की गयी है। यह पुस्तक जनजातिय विकास के बहुमुखी उपागम व रणनीतियों को प्रस्तुत करता है।

- सार्थक सेनगुप्ता (2002) ने पेपर संग्रह Tribal Studies in North East India में जनजातियों की जनसंख्या, समाज, संस्कृति, स्वास्थ्य व नृजातीय अध्ययन प्रस्तुत किया।

- N.K. Vaid (2004) ने अपनी iqfLrd Who care for Tribal Development में जनजातिय विकास के नए अन्तदृष्टि प्रस्तुत किया है। यह जनजातिय विकास की प्रमुख्य योजनाओं का भी जिक्र किया है।

- Govind Chandra Rath. (2006) ने अपनी पुस्तिक Tribal Development in India में पिछले 50 वर्षों में जनजातियों के विकास का वर्णन किया है।

- Devendra Thakur and D.N. Thakur (2009) ने अपनी पुस्तिक Tribal Development & Planning ने विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनजातियों के लिए सरकारी प्रयासों को दिखाया गया है।

Amit Kr. Patel

- Bhopinder Singh (2007) ने शोध पेपर Tribal Scenario in the Context of Economic Liberation & Globalisation में सरकारी योजनाओं और उसके अपूर्ण कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला।

- Mauleena Bera Pattanayak (20013) ने अपने लेख A Study of Educational awareness among Tribal Parents in the Salboni इसवबा वश्रिंदहसम डींस में सरकारी योजनाओं के सुधार प्रस्तुत किये गये है।

- Srinivasan Ram Chandran (2012) ने अपनी पुस्तिक Tribal Development Programs in India में लेखक ने जनजातियों की निरक्षरता व गैर जागरूकता का जिक्र किया है।

- N. K. Panda (2006) ने अपनी पुस्तिक Policies Programmes and Strategies for Tribal Development में ओडिया राज्य की जनजातिय समस्याओं का जिक्र किया है।

- Jayanta Chaudhary (2009) ने अपने लेख Efforts of Tribal Development in Tripura : An Assessment में लेखन ने सरकारी नियोजन के गुण व दोषों का वर्णन किया है।

- M. Gopinath Reddy and Anil Kumar ने अपनी पुस्तिक Political Economy of Tribal Development: A case Study of Andra Pradesh में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अनुदान व उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है।

- Luke Daimary (2009) ने अपने शोध लेख Major Hurdels to Tribal Development में जनजातियों की ऋण ग्रस्तता, शैक्षिक पिछड़ापन व भ्रष्टाचार का जनजातियों के विकास में जिक्र किया है।

- K.B. Jamatia (2009) ने अपने शोध लेख Prespective of Tribal Development : Issues and Challenges में गरीबी को समाप्त करने जीवन की गुणवत्ता सुधारने, शोषण, संघर्ष व निरक्षतरता को दूर करने और प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग पर बल दिया है।

- Vidya Das (2003) ने अपने लेख Democratic Governance in Tribal Regions, EPW में जनजातिय क्षेत्रों में जनतंत्रात्मक भूमिका का वर्णन किया है।

Amit Kr. Patel

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी सीमांत भाग में स्थित है। इस जनपद की सीमायें क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से संलग्न है यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से द्वितीय सबसे बड़ा जनपद है। अध्ययन क्षेत्र का अक्षांशीय विस्तार 23°51′ उत्तर से 25°32′ उत्तर अक्षांश के मध्य तथा देशान्तरीय विस्तार 82°72′ पूरब से 83°33′ पूरब देशान्तर के मध्य है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं चन्दौली जिलो से सीमांकित होती है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर है। जो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2. 80 प्रतिशत है। इस अध्ययन क्षेत्र में 4 तहसीलें, 10 विकास खंण्ड व 67 न्याय पंचायत है, कुल 22 पुलिस स्टेशन है। अध्ययन क्षेत्र में कुल ग्राम पंचायाते 501 व गाँव 1443 है। कुल आबाद गांवो कि संख्या 1387 व गैर आबाद गांवो की संख्या 39 है जिसकी कुल आबादी 18,62,559 है। जनपद का लिंगानुपात 918 महिला प्रति हजार पुरुष हैं। इसका जनघनत्व 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जिसकी 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति है। सम्पूर्ण जनसंख्या की साक्षरता 64.03 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 74.92 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 52.14 प्रतिशत है। सोनभद्र जनपद में मुख्यतः गोंड, खैरवार, बैगा, पनिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइयॉ व परेहिया जनजाति निवास करती है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या कृषि, कृषि श्रमिक व फैक्ट्री मजदूर है।

Amit Kr. Patel

Location Map

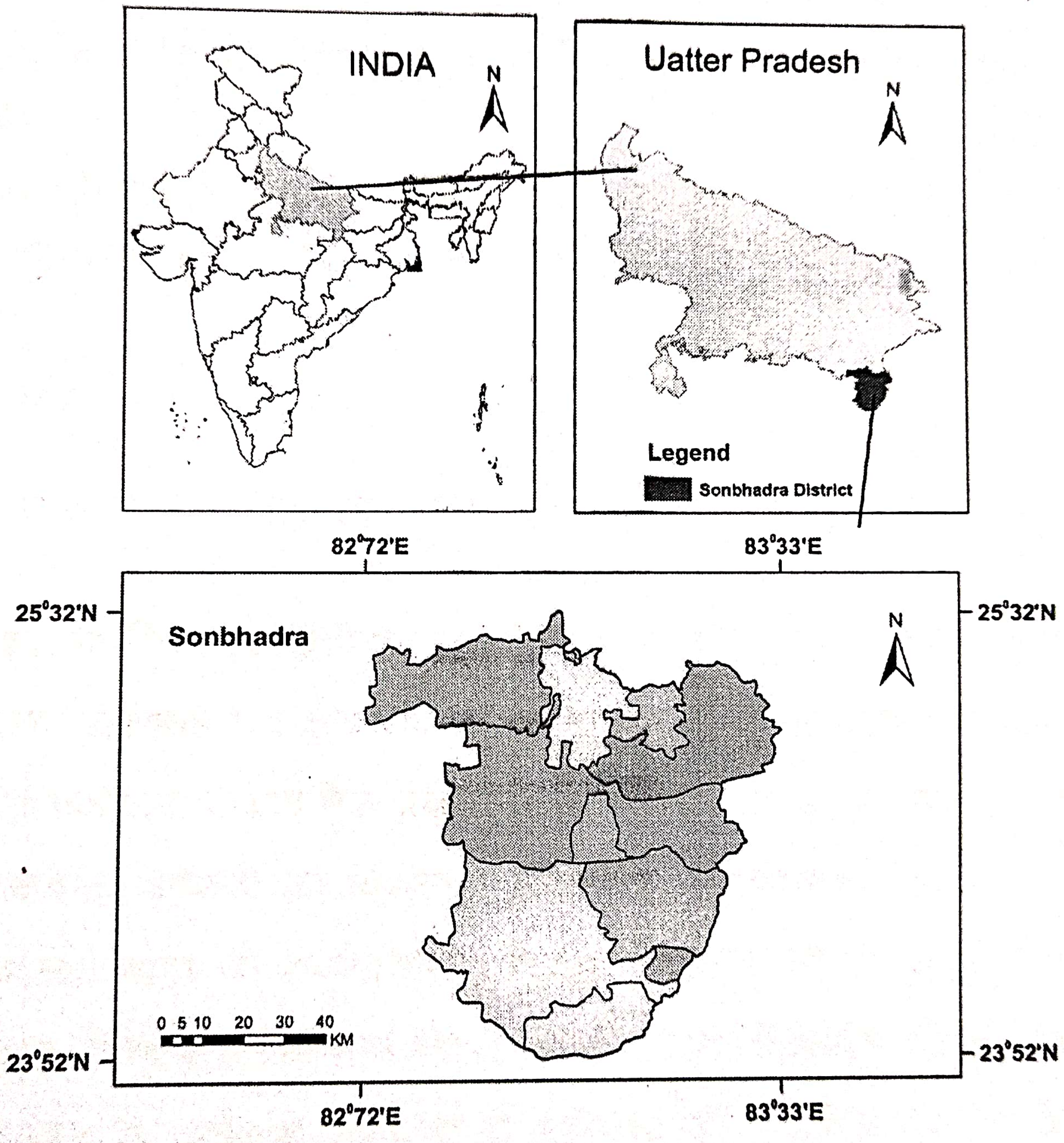

Amit Kr. Patel

शोध उद्देश्य

यहां शोध उद्देश्यों का विवरण निम्नलिखित है:–

- अध्ययन क्षेत्र में जनजातियों के समक्ष भौतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं को रेखांकित करना।
- अध्ययन क्षेत्र में सरकारी योजनाओं और नीतियों का जनजातीय विकास में योगदान की समीक्षा करना।
- अध्ययन क्षेत्र जनपद सोनभद्र में जातिय समस्याओं एवं चुनौतियों का मूल्यांकन करना।
- जनपद सोनभद्र में निवास करने वाली जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझावों को रेखांकित करना।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्न विधि तंत्र उपयोगी है।

प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों पर आधारित होगा। प्राथमिक आकड़ों का संग्रह प्रश्नावली, साक्षात्कार व क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से किया जायेगा। द्वितीय आकड़ों का संग्रह सरकारी प्रकाशन, अकादमिक प्रकाशन, जनगणना आकड़ा व अन्य प्रासंगिक स्रोतों से प्राप्त किया जायेगा। आंकड़ों का विश्लेषण, मात्रात्मक व गुणात्मक विश्लेषण से किया जायेगा। मात्रात्मक डाटा को अंकगणितीय, रेखीय व ग्राफीय चित्रण करके सहसम्बन्ध विश्लेषण, कारक विश्लेषण, प्रतिगमन विश्लेषण व प्रतिशत विश्लेषण किया जायेगा। गुणात्मक विश्लेषण में साक्षात्कार आंकड़ा के मुख्य विषयों व प्रतिरूप की पहचान के लिए विषयगत विश्लेषण का उपयोग किया जायेगा। सरकारी संसाधनों, आदिवासी बस्तियों और विकास संकेतकों के वितरण सहित भौगोलिक आंकड़ा के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी0आई0एस0) का प्रयोग भी यथा सम्भव किया जायेगा।

Amit Kr. Patel

शोध का आपेक्षित परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न अपेक्षित शोध परिणाम हो सकते हैं

1. राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा जनजातियों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही होगी ।
2. जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास और विभिन्न सरकारी योजनाओं में सकारात्मक संबंध होगा।
3. विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा जनजातियों में शैक्षिक उन्नयन हुआ होगा।
4. विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा जनजातियों एवं अन्य सामाजिक समूह के आर्थिक असमानता में कमी आ रही होगी।
5. सरकारी कार्यक्रमों द्वारा जनजातियों के उपभोग स्तर एवं जीवन स्तर में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- N.K.Vaid, **Who Cares for Tribal Development,** Mittal Publications, New Delhi, 2004, pp.20-21
- Ashutosh Thakur, **Tribal Development and its paradoxes**, Authors Press, New Delhi, 2001.
- Nishakar Panda, Tribal Commonalities and Under **Development: An Interface**,Serials Publications, New Delhi, 2009.
- Deogaonkar, S.G. (1992) *Tribal Development Plan Implementation and Evaluation,* New Delhi: Publishing Company.
- Rath, Govinda Chandra (2006), *Tribal Development in India,* New Delhi; Sage Publications.

Amit Kr. Patel

- Sengupta, Sarthak (2002), *Tribal Studies in North East India*, New Delhi: Mittals Publication.
- Singh, C.P. (1994), *Tribal Development Administration,* New Delhi: Mittals Publication.
- Vaid, N. K. (2004), *Who Cares for Tribal Development,* New Delhi; Mittals Publication.
- Basu, S. (2000). *Dimensions of Tribal Health in India. 23*(2), 61–70.http://medind.nic. in/
- Ramchandran, S. (2012). *Tribal Development Programmes in India.* New Delhi: Abhijeet Publications.
- Panda, N. K. (2006). *Policies Programmes and Strategies for Tribal Development.* Delhi:Kalpaz publications.
- Misal Dilip M. **Tribal Development Policies in India - An Overview**,International Journal of Humanity and Social Sciences, Volume 5, Issue 1, 2016.
- D. Janaki, **Socio-Economic Conditions of Tribal Women in South India,** Dhana Publications, Chennai, 2000.
- K.Govindaraj, **Tribal Development Programmes in Kalvarayan Hills**,International Journal of Pharmaceutical and Biological Archives, Vol.5, No.3,2014.
- Basant Mehta; Prakash Chandra Mehta, **Dynamics of Tribal Development**, Anmol Publications, Pvt, Ltd., New Delhi, 2000, pp.2-3.
- Nishakar Panda, **Tribal Commonalities and Under**
- **Development: An Interface**,Serials Publications, New Delhi, 2009.
- Singh, A. K. (1994). *Approaches to Tribal Development.* New Delhi: Sarup & Sons.
- Sundaram, A. (2013); *Socio-Economic Development of Tribals in Mizoram*; New Delhi;V.L. Media Solutions.
- Singh, R. (2000), *Tribal Beliefs, and Insurrections*, New Delhi; Anmol Publications Pvt.Ltd.

Amit Kr. Patel

- N. Pathak N. and B. V. Gour (2001), *Tribal Self-Rule and Natural ResourceManagement,* Kalpavriksh and International Institute of Environment and Development, New Delhi.

DrillBit

The Report is Generated by DrillBit Plagiarism Detection Software

Submission Information

Author Name	Amit Kumar Patel
Title	Sarkari Yojanayen Evem Janjatiye Vikas: Janpad Sonbhadra Ka Ek Bhaugolik Adhyayan
Paper/Submission ID	3608180
Submitted by	santoshauprtou@gmail.com
Submission Date	2025-05-13 13:37:55
Total Pages, Total Words	11, 2246
Document type	Synopsis

Result Information

Similarity **4 %**

Sources Type

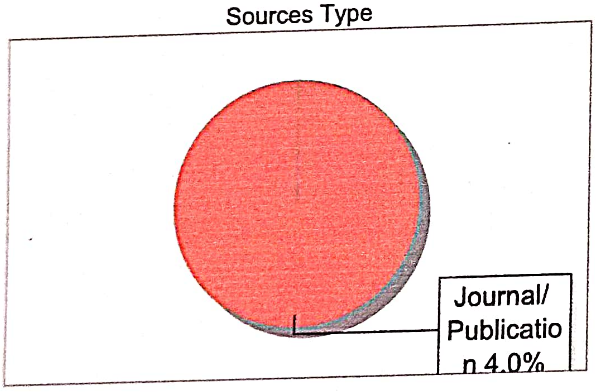

Report Content

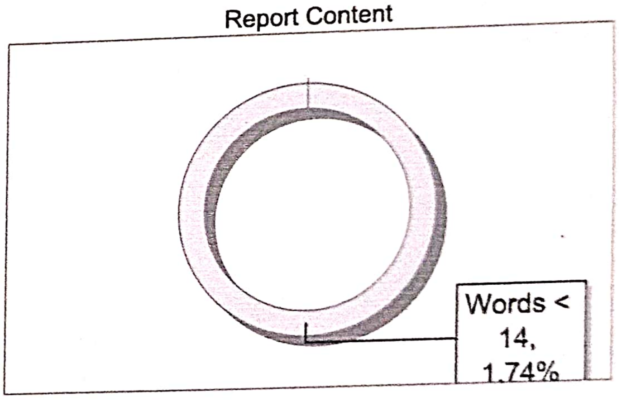

Exclude Information

Quotes	Not Excluded
References/Bibliography	Not Excluded
Source: Excluded < 14 Words	Not Excluded
Excluded Source	0 %
Excluded Phrases	Not Excluded

Database Selection

Language	Non-English
Student Papers	Yes
Journals & publishers	Yes
Internet or Web	Yes
Institution Repository	Yes

A Unique QR Code use to View/Download/Share Pdf File

Amit Kr. Patel

DrillBit

DrillBit Similarity Report

4	4	A	A-Satisfactory (0-10%) B-Upgrade (11-40%) C-Poor (41-60%) D-Unacceptable (61-100%)
SIMILARITY %	MATCHED SOURCES	GRADE	

LOCATION	MATCHED DOMAIN	%	SOURCE TYPE
1	www.education.gov.in	2	Publication
2	Thesis Submitted to Shodhganga, shodhganga.inflibnet.ac.in	1	Publication
3	byjus.com	1	Publication
4	egyankosh.ac.in	<1	Publication

Amit Kr. Patel